सत्यमेव जयते

Department of Justice
Ministry of Law and Justice
Government of India

विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम 2022-2024

न्याय तक सार्वभौमिक पहुंच

श्री अर्जुन राम मेघवाल
माननीय राज्य मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार)

अनुच्छेद 39ए
सभी के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करना

एसडीजी 16
सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना

न्याय विभाग की यात्रा का दशक
कानूनी अधिकारिता की ओर

A2J-UNDP परियोजना (2009 - 2012)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से सीमांत लोगों के लिए न्याय तक पहुंच

भौगोलिक विस्तार

बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश

A2J-NEJK प्रोजेक्ट (2012 - 2017)

- विचाराधीन कैदियों सहित गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना
- गांव आधारित कानूनी क्लिनिक स्थापित करने में विधि महाविद्यालयों/एलएसए के माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करना
- सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना

भौगोलिक विस्तार

असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख

पहले चरण की उपलब्धियां

- **20,672+** पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षित एवं संवेदनशील बनाया गया
- **1,400** गाँव बुरास और बूढ़ी औपचारिक न्याय संरचना के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए संवेदनशील बने
- नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में एसआईआरडी के साथ सहयोग करना
- **15500+** कानूनी जागरूकता अभियान और संवेदीकरण अभियान आयोजित किए गए

दूसरे चरण की उपलब्धियां

- **7.12 लाख** लाभार्थियों को कवर किया गया
- **4390** कानूनी साक्षरता/कानूनी जागरूकता अभियान आयोजित किए गए
- **1,884** ग्राम प्रधानों को प्रशिक्षित एवं संवेदनशील बनाया गया
- **8.3 लाख** 26 भाषाओं में 69 कानूनों पर आईईसी सामग्री
- **20,000+** मास्टर ट्रेनर्स
- **158** सामुदायिक स्तर पर कानूनी सहायता क्लीनिक स्थापित करना

विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम के लिए 5-आयामी रणनीति

1. मंत्रालयों और निजी भागीदारों के साथ अभिसरण
2. प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना
3. फील्ड स्तर के पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण
4. समवर्ती मूल्यांकन
5. मूल्यांकन के लिए मापने योग्य संकेतक विकसित करें

अखिल भारतीय स्तर पर कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता के क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए *2021-2024* के दौरान *16* एजेंसियों को शामिल किया गया है।

सरकार/स्वायत्त/अनुसंधान निकाय

डॉ. अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, पांडिचेरी
परियोजना: 'NYAYA OLI परियोजना-युवाओं में कानूनी जागरूकता फैलाना'

महत्वपूर्ण पहल:
- स्कूलों और कॉलेजों में इंटरैक्टिव कार्यशालाएँ आयोजित करना
- इन्फोग्राफिक्स और वीडियो सहित आयु-उपयुक्त शैक्षिक सामग्री विकसित करना

आउटरीच: **4,698**
Website : www.pondiuni.edu.in

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
परियोजना: "भारत में पैरालीगल प्रैक्टिस को मजबूत करना"। पैरालीगल वालंटियर का क्षमता निर्माण

महत्वपूर्ण पहल:
- भारत में पैरालीगल चिकित्सकों का एक कैडर विकसित करना

आउटरीच: **1,579**
Website : www.ignou.ac.in

मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिलांग, मेघालय
परियोजना: 'सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से न्याय तक पहुंच बढ़ाना'

महत्वपूर्ण पहल:
- दो जिलों री-भोई और पश्चिमी गारो हिल्स में 1933 गांवों के साथ 11सी और आरडी ब्लॉकों को कवर करने वाले 800 मुखियाओं/नोकमाओं/साइम्स का प्रशिक्षण

आउटरीच: **3,399**
Website : www.mslsa.gov.in

अरुणाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
परियोजना: 'परंपरागत ग्राम परिषद प्रणाली की प्रथाओं और भारत के औपचारिक कानूनों के बीच तालमेल'

महत्वपूर्ण पहल:
- 1367 गाँव बुराह और गाँव बूढ़ी को संवेदनशील बनाया गया
- E1T10 अभियान: प्रत्येक को 10 और प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया

आउटरीच: **6,666**
Website : www.nalsa.gov.in

सिक्किम राज्य महिला आयोग
परियोजना: 'महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों पर क्षमतावर्धन'

महत्वपूर्ण पहल:
- प्रासंगिक सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर टॉक शो।
- महिलाओं से संबंधित कानूनों पर हितधारकों की कानूनी जागरूकता

आउटरीच: **1,55,606**
Website : www.sikkim.gov.in

जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान, मणिपुर

परियोजना: 'बाल यौन शोषण के खिलाफ हितधारकों का प्रशिक्षण और संवेदीकरण'

महत्वपूर्ण पहल:

- संवेदीकरण कार्यशालाएं और प्रशिक्षण मॉड्यूल
- प्रशिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण के उपाय
- पीड़ितों और उनके परिवारों को मनोसामाजिक सहायता

आउटरीच: **2,605**

Website : www.jnims.nic.in

लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी, असम

परियोजना: 'पूर्वोत्तर राज्यों की पारंपरिक प्रथाओं का दस्तावेजीकरण'

महत्वपूर्ण पहल:

- जीवंत संस्कृति और जनजातियों के प्रथागत कानूनों की अनूठी विशेषताओं का दस्तावेज़ीकरण

आउटरीच: **304**

Website : www.ghconline.gov.in

नागरिक सामाजिक संगठन/निजी निकाय

सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसाइटी, जयपुर, राजस्थान

परियोजना: 'महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देना'

महत्वपूर्ण पहल:

- क्षेत्रीय विशेषज्ञों के साथ साझेदारी करना
- अग्रिम पंक्ति के स्वयंसेवकों की क्षमता निर्माण

आउटरीच: **58,990**

Website : www.cecoedecon.org.in

छाया विज्ञापन और संचार प्रा. लिमिटेड, भुवनेश्वर

परियोजना: 'डिजिटल लीगल लिटरेसी और सामुदायिक कानूनी जागरूकता'

महत्वपूर्ण पहल:

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाएं
- क्षमता निर्माण कार्यक्रम

आउटरीच: **3,98,832**

Website : www.shadowadd.com

राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों

एनएलएसआईयू, बेंगलुरु

परियोजना: 'डिजिटल कानूनी साक्षरता-प्रसार और मूल्यांकन'

महत्वपूर्ण पहल:

- कानूनी साक्षरता के लिए समर्पित YouTube चैनल CEERA-NLISU-DoJ की डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करें
- ज़मीनी स्तर पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना
- राष्ट्रीय स्तर पर लीगल एड कम्पटीशन का आयोजन
- कानूनी साक्षरता के लिए पिक्चर बुक का प्रकाशन

आउटरीच: **6,60,300**

Website : www.nls.ac.in

एनएलयू, नई दिल्ली

परियोजना: 'अधिकारों का ज्ञान उन्नति की पहचान'

महत्वपूर्ण पहल:

- महिला के विरुद्ध क्रूरता के मामलों में कानूनी निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना
- सामुदायिक भागीदारी का हाइपर-लोकल ग्रासरूट मॉडल तैयार करें

आउटरीच: **1,613**

Website : www.nludelhi.ac.in

एनएलआईयू, भोपाल

परियोजना: 'राष्ट्रीय स्तर की डिजिटल कानूनी साक्षरता - डिजाइन, विकास, प्रबंधन और परीक्षण - ई न्यायगंगा'

महत्वपूर्ण पहल:

- डिजिटल कानूनी साक्षरता पर डिजिटल आईईसी सामग्री का विकास और प्रबंधन
- डिजिटल सामग्री के निर्माण की सुविधा के लिए विभिन्न राष्ट्रीय और निजी लॉ कॉलेजों के साथ 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए

आउटरीच: **6,173**

Website : www.nliu.ac.in

ग्रामीण विकास के राज्य संस्थान

एसआईआरडी, पुणे, महाराष्ट्र

परियोजना: 'महाराष्ट्र के 4 आकांक्षी जिलों की 100 ग्राम पंचायतों में विधि दूतों का प्रचार'

महत्वपूर्ण पहल:

- ग्राम स्तर पर 700 विधिदूतों की पहचान और क्षमता निर्माण
- YASHADA के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कानूनी साक्षरता सामग्री और उपकरण का निर्माण
- वाशिम, नंदुरबार, गढ़चिरोयल और ओस्मानाबाद

आउटरीच: **2,911**

Website : www.yashada.org

बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, पटना

परियोजना: 'बिहार के 7 आकांक्षी जिलों की ग्राम पंचायतों में 700 विधि मित्रों का प्रचार'

महत्वपूर्ण पहल:

- 700 विधि मित्रों का क्षमता निर्माण
- आईईसी सामग्री और सेवाप्रदाता प्रशिक्षण किट विकसित करना
- औरंगाबाद, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज

आउटरीच: **1,345**

Website : www.bipard.bihar.gov.in

अब्दुल नज़ीर साहब राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायत राज, मैसूर, कर्नाटक

परियोजना: 'मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार'

महत्वपूर्ण पहल:

- पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सेटकॉम के द्वारा
- प्रशिक्षण सत्रों का वीडियो/प्रिंट प्रलेखन सुनिश्चित करें
- आईईसी किट और प्रशिक्षण मैनुअल विकसित करें

आउटरीच: **95,230**

Website : www.sirdmysuru.karnataka.gov.in

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

परियोजना: 'कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन'

महत्वपूर्ण पहल:

- डाटा बैंक का डिजिटल भंडार विकसित करना
- आउटपुट और परिणामों के लिए डैशबोर्ड विकसित करें

आउटरीच: **18**

Website : www.iipa.org.in

हमारे 16 भागीदार: प्रभाव क्षेत्र

भौगोलिक विस्तार

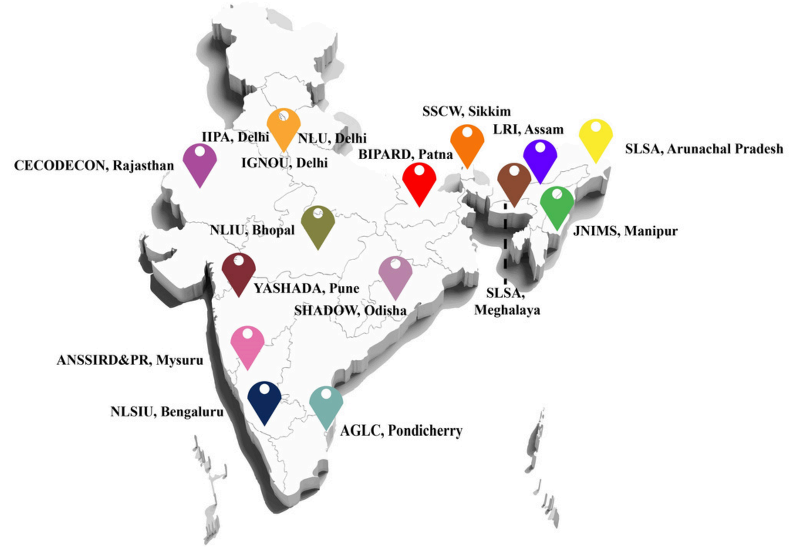

प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (दिशा)
एक्सेस टू जस्टिस डिवीज़न,
डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस
मानसिंह रोड, जैसलमेर हाउस
नई दिल्ली - 110011
Ph: 011-23072147, Ext 292 & 257

www.doj.gov.in/